(a) whether the telephones of the subscribers against whom outstanding dues are more than rupees one lakh have since been disconnected and if not, what are the reasons therefor;

(b) what steps are proposed to be taken to collect these dues;

(c) whether Government are aware that General Managers gave oral instructions not to disconnect the telephones of such defaulting subscribers and if so, whether Government propose to issue instructions against such practice; and

(d) the number of cases in which such orders have been issued not to disconnect telephone during the last three years, yearwise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) The subscribers who had more than Rs. one lakh outstanding as telephone dues against them as on 1-7-1985 in respect of teleprone bills issued upto 31-3-1985 were as below:-

Sl. No.	*Name of Subscribers*
1.	Shri B. N. Passari:
2.	Shri M. L. Jaggi.
3.	M/s. Ram Kishan Kulwant Rai.
4.	General Secretary A.I.C.C.
5.	Embassy of Zaire.
6.	Shri Som Nath.
7.	Shri Manjit Singh.

Telephones of subscribers at serial 5, 6 and 7 have already been disconnected. Telephones of subscribers at serial 1,2 and 3 could not be disconnected as the cases are sub-judice.

In respect of case at serial 4 there had been complaint of excess billing. The case has beeen investigated and found that there was no justification for grant of any rebate. The subscriber has been advised to pay the bills. The payments are being pursued vigorously.

(b) The cases under arbitration or in the court have to wait for the final decision in the case to enable recovery from the subscriber. As regards, telephone of the subscriber at serial 4, the case is being pursued. In the case of the dues outstanding against the Embassy of Zaire, the case has been taken up with the Embassy concerned and also through the Ministry of External Affairs for recovery of dues. In the remaining two cases chances of recovery are not bright as the subcribers are absconding and the cases are being investigated further.

(c) The reasons for non-disconnection of telephones have already been indicated above. General Managers have not given any oral instruction for non disconnection of telephones.

(d) In view of (c) above, does not arise.

बिजली की खपत और उत्पादन में अन्तर

*392. **श्री घनश्याम सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की खपत और उत्पादन में इस समय कितना अन्तर है ;

(ख) देश में विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस समस्या का हल कब तक निकाल लेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश में इस समय औसत दैनिक विद्युत उत्पादन लगभग 473 मिलियन यूनिट है, जबकि इसकी तुलना में अनुमानित औसत आवश्यकता लगभग 516 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है ।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सातवीं योजना में 34,273 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह प्रस्ताव है कि 22,245 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए तथा मौजूदा क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जाए। पारेषण और वितरण हानियों को कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक 1442 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई गई है। कोयले पर आधारित यूनिटों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। अप्रैल से नवम्बर 1985 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 50.3 प्रतिशत था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 45.9 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश में, सातवीं योजना में राज्य क्षेत्र में 1794 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है तथा मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों का भी नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा।

(ग) निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

Survey on relief and rehabilitation work relating to Bhopal gas victims

@*393. SHRI VIRENDRA VERMA:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press report which appeared in the *Hindustan Times* of the 28th September, 1985 regarding the findings of a survey conducted among the Bhopal gas victims by the Students Federation of India in collaboration with the Madhya Pradesh Vigyan Sabha and the Delhi Science Forum with regard to the relief and rehabilitation work; and

(b) if so, what action Government have taken on the basis of the findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) It appears that the survey conducted was only a sample survey of 4000 households. The Government of Madhya Pradesh have undertaken a comprehensive socio-economic, survey, covering about 80,000 families in the thirty affected wards. The information obtained through this socio-economic survey is being computerised and is used by the State Government to provide relief and rehabilitation facilities to the affected population, which would, *inter alia*, cover the reported findings of the sample survey.

*394. [*Transfered to the 18th December, 1985.*]

देश में गैस की उपलब्धता

*395. **श्री जगदंबी प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस के संबंध में अब तक किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार देश में कितनी गैस उपलब्ध है और देश में इसकी कितनी मांग है; और

(ख) क्या यह सच है कि असम के क्षेत्रों में गैस उपलब्ध है लेकिन उपलब्ध गैस को लेने वाला कोई नहीं और यदि हां, तो उन व्यक्तियों को गैस उपलब्ध कराने के लिये जिन्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) 1-1-1985 को देश में प्राकृतिक गैस के प्राप्य शेष भंडारों का अनुमान करीब 479 बिलियन घन मीटर लगाया गया है। गैस का प्रयोग उर्वरकों, विद्युत और पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए और उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस की खपत क्षमता गैस के उत्पादन परिवहन और

@Previously Starred Question 213 transferred from the 3rd December, 1985.